सिविल लेखा दिवस(civil accounts day)

केंद्र सरकार ने 1976 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में बहुत बड़े सुधार की पहल की। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के लेखें तैयार करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्य अलग कर दिए गए। लेखा कार्य सीधे कार्यकारी के नियंत्रणाधीन लाया गया। परिणामस्वरूप, भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) की स्थापना की गई। आईसीएएस का गठन भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा (आईए तथा एएस) में से प्रारम्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करके किया गया। बाद में, संसद द्वारा संघीय लेखा विभागीकरण (कार्मिक स्थानांतरण) अधिनियम, 1976 पारित किया गया और 8 अप्रैल, 1976 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान की। अधिनियम 01 मार्च, 1976 से लागू माना गया। तदनुसार, आईसीएएस प्रति वर्ष 1 मार्च को 'सिविल लेखा दिवस' के रूप में मनाता है। आईसीएएस के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इसका बहुत विस्तार हुआ है और अब यह केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।